JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के छोटे शहरों में युवा उद्यमिता: अवसर, स्थानीय समाधान और क्षेत्रीय आर्थिक विकास

डॉ. मीना कीर
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य
प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
शासकीय नर्मदा महाविद्यालय, नर्मदापुरम (म.प्र.)

शोध सारांश (Abstract)

भारत का आर्थिक परिदृश्य वर्तमान में एक संरचनात्मक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।महानगर से परे, टियर–2 और टियर–3 शहर आर्थिक गतिविधियों और नवाचार के नए केंद्र बनकर उभर रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र भारत के छोटे शहरों में युवा उद्यमिता के उभार, इसके समक्ष उपलब्ध अवसरों, स्थानीय चुनौतियों के समाधान और क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि डिजिटल समावेशन, बेहतर कनेक्टिविटी और स्थानीय संसाधनों के मूल्य संवर्धन ने युवाओं को महानगरों की ओर पलायन करने के बजाय स्व–रोजगार और रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित किया है। अध्ययन में सरकारी पहलों, पूंजीगत प्रवाह और ढांचागत चुनौतियों का मूल्यांकन करते हुए स्थानीय आर्थिक तंत्र को सुदृढ़ करने के व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द (Keyword): युवा उद्यमिता, टियर–2/3 शहर, क्षेत्रीय आर्थिक विकास, स्थानीय समाधान, डिजिटल समावेशन, एमएसएमई (MSME)।

1. प्रस्तावना (Introduction)

पारंपरिक रूप से भारत में उद्यमशीलता और स्टार्टअप संस्कृति को बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली–एनसीआर और हैदराबाद जैसे महानगरों तक ही सीमित माना जाता था। हालांकि, पिछले दशक में सस्ते इंटरनेट, यूपीआई (UPI), लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और विकेंद्रीकृत बुनियादी ढांचे ने इस धारणा को बदला है। भारत की लगभग 65: आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, और इस जनसांख्यिकीय लाभांश (Demographic Dividend) का एक बड़ा हिस्सा छोटे शहरों और कस्बों में निवास करता है।

नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर, कोयंबटूर, सूरत जैसे टियर–2 और टियर–3 शहरों के युवा उद्यमी अब केवल पारंपरिक खुदरा व्यापार तक सीमित नहीं हैं। वे कृषि–तकनीक (Agri&tech), खाद्य प्रसंस्करण, स्थानीय शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और हाइपरलोकल सेवाओं में नवाचार ला रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल क्षेत्रीय आय असमानता को कम कर रही है, बल्कि अनियंत्रित ग्रामीण–शहरी पलायन पर भी प्रभावी रोक लगा रही है।

2. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. भारत के छोटे शहरों (टियर–2 और टियर–3) में युवा उद्यमिता के प्रमुख प्रेरकों एवं अवसरों की पहचान करना।
2. स्थानीय समस्याओं के समाधान में युवा उद्यमियों द्वारा अपनाए गए नवाचारों का विश्लेषण करना।
3. क्षेत्रीय आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण पर युवा उद्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना।
4. छोटे शहरों के उद्यमियों के समक्ष आने वाली वित्तीय, ढांचागत और तकनीकी बाधाओं को रेखांकित करना तथा नीतिगत सुझाव देना।

3. शोध प्रविधि (Research Methodology)

प्रस्तुत शोध पत्र विवरणात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन हेतु डेटा मुख्य रूप से द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) से संकलित किया गया है, जिनमें शामिल हैं, नीति आयोग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), और डीपीआईआईटी(DPIIT) की वार्षिक रिपोर्ट। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़े। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स, श्वेत पत्र (White Papers) और उद्योग रिपोर्ट (जैसे NASSCOM] Startup India MsVkcsl)। विभिन्न राज्यों (विशेष रूप से मध्य प्रदेश) के स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के केस अध्ययन।

4. छोटे शहरों में युवा उद्यमिता के उभरते अवसर (Emerging Opportunities)

छोटे शहरों में उद्यम स्थापित करने के कई तुलनात्मक लाभ हैं जो महानगरों में उपलब्ध नहीं हैं

क्षेत्र (Sector)	प्रमुख अवसर	स्थानीय प्रासंगिकता
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (Agri &Tech & Food Processing)	शीत भंडारण (Cold Chain), जैविक उत्पाद पैकेजिंग मृदापरीक्षण एवं ड्रिप इरगेशन सेवाएं।	प्रत्यक्ष कृषि उपज उपलब्धता, कम परिवहन लागत
हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स व ई– कॉमर्स	अंतिम मील तक डिलीवरी (Last & mile delivery), स्थानीय उत्पादों का ऑनलाइन विपणन।	क्षेत्रीय उपभोक्ताओं की बढ़ती डिजिटल मांग।
पारंपरिक शिल्प एवं हथकरघा	डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (ODOP/ ONDC) के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच।	स्थानीय कारीगरों को बिचौलियों से मुक्ति, उच्च मार्जिन।
शिक्षा और स्वास्थ्य (Education &Tech & Health &Tech)	किफायती डायग्नोस्टिक्स, स्थानीय कौशल विकास केंद्र।	महानगरों की तुलना में सस्ती सेवाओं की भारी मांग।

लागत दक्षता (Cost advantage) महानगरों की तुलना में छोटे शहरों में वाणिज्यिक भूमि का किराया 60–70ः तक कम होता है और परिचालन लागत (Operational Cost) न्यूनतम रहती है। स्थानीय प्रतिभा का संधारण (Talent Retention): स्थानीय इंजीनियरिंग और कॉलेजों से उत्तीर्ण स्नातक कम वेतन पर स्थानीय स्तर पर कार्य करने के इच्छुक रहते हैं, जिससे शुरुआती पूंजी की बचत होती है।

5. स्थानीय समाधान: जमीनी नवाचार (Local Solutions: Grounded Innovations)

छोटे शहरों के युवा उद्यमी (Glocal & Global Vision with Local Action) मॉडल पर कार्य कर रहे हैं। उदाहरण स्वरूप संसाधन–आधारित मूल्य संवर्धनरू नर्मदापुरम जैसे कृषि–प्रधान जिलों में युवा केवल गेहूं या सोयाबीन बेचने के बजाय श्ग्रेडिंगश, श्ब्रांडिंगश और सीधे उपभोक्ता तक पैकेज्ड आटा व तेल पहुंचाने वाले उद्यम शुरू कर रहे हैं। ओएनडीसी (ONDC) और ई–कॉमर्स का एकीकरण: स्थानीय व्यापारी वर्ग को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़कर युवा डिजिटल एजेंसियां बना रहे हैं, जिससे स्थानीय किराना और कपड़ा व्यापारियों का कारोबार बढ़ रहा है।चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy)रू कृषि अपशिष्ट (पराली, छिलके) से बायो–कंपोस्ट, पैकेजिंग सामग्री या बायो–कोल ब्रिकेट्स बनाने के सफल मॉडल युवाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।

6. क्षेत्रीय आर्थिक विकास पर प्रभाव (Impact on Regional Economic Development)

पूंजी का स्थानीय संचलन (Local Capital Circulation)रू जब कोई स्थानीय उद्यम फलता–फूलता है, तो अर्जित लाभ स्थानीय बैंकों में जमा होता है और पुनः उसी क्षेत्र में निवेशित होता है, जिससे "आर्थिक गुणक प्रभाव" (Economic Multiplier Effect) उत्पन्न होता है।कुशल रोजगार सृजन: टियर–3 शहरों में एक सफल उद्यम कम से कम 5 से 25 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करता है, जिससे गैर–कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। महिला उद्यमिता को बढ़ावारू स्थानीय स्तर पर उद्यम शुरू होने से महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुलभ कार्य वातावरण तैयार हुआ है। मुद्रा योजना और स्टैंड–अप इंडिया ने युवतियों को स्वतंत्र व्यवसाय शुरू करने में सक्षम बनाया है।

7. प्रमुख चुनौतियाँ (Key Challenges)

प्रारंभिक उद्यम पूंजी (Seed Capital) का अभाव : औपचारिक बैंकिंग संस्थान आज भी संपार्श्विक (Collateral) सुरक्षा की मांग करते हैं, जिससे नवीन विचारों वाले युवाओं को पर्याप्त ऋण नहीं मिल पाता। छोटे शहरों में एंजेल निवेशक (Angel Investors) नगण्य हैं। मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन की कमी: अधिकांश इन्क्यूबेशन केंद्र महानगरीय विश्वविद्यालयों या आईआईटी/आईआईएम तक सीमित हैं। जिला स्तर के शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों में यह व्यवस्था अभी प्रारंभिक अवस्था में है। बाजार की सीमित क्रय शक्ति: स्थानीय बाजार में उच्च–मूल्य वाली वस्तुओं या प्रीमियम सेवाओं के लिए सीमित ग्राहक आधार होता है, जिससे उद्योगों को बाहरी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है। नियामक अनुपालन जटिलताएँ: जीएसटी रिटर्न, ट्रेड लाइसेंस, श्रम कानून प्रमाणन जैसी विधिक प्रक्रियाओं के लिए छोटे शहरों में विशेषज्ञ सलाहकारों का अभाव होता है।

8. नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

कॉलेज–आधारित इन्क्यूबेशन केंद्रः "जिला स्तर पर छोटे शहरों में जहां बहुत अधिक साधन उपलब्ध नहीं है वहां स्टार्टअप्स या उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन एवं इनोवेशन हब" स्थापित किए जाने चाहिए। ऋण गारंटी योजनाओं का विस्तारः क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) की प्रक्रियाओं का सरलीकरण जिला स्तर के ग्रामीण और वाणिज्यिक बैंकों में सुनिश्चित हो।कौशल और मेंटरशिप क्लस्टरः पूर्व सफल उद्यमियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और उद्योगपतियों का एक जिला–स्तरीय मेंटरशिप पैनल बनाया जाए जो नवोदित उद्यमियों को मार्गदर्शन दे। स्थानीय खरीद प्राथमिकताः जिला स्तर की सरकारी खरीद में 20–25ः अनिवार्य कोटा स्थानीय पंजीकृत युवा उद्यमियों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए।छोटे शहरों में युवा कृषि आधारित उत्पादों को किस प्रकार निर्यात योग्य बना सके इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। अंतर राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों में मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता है जिससे उपज का उचित मूल्य मिल सके।

9. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग केवल 8–10 महानगरों से होकर नहीं गुजरता; इसकी वास्तविक आधारशिला देश के छोटे शहर और कस्बे हैं। टियर–2 और टियर–3 शहरों के युवा अपनी आकांक्षाओं को स्थानीय संसाधनों और डिजिटल तकनीक के साथ जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं। यदि नीतिगत स्तर पर वित्तीय पहुंच और कौशल विकास की बाधाओं को दूर कर दिया जाए, तो छोटे शहरों की युवा उद्यमिता समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास का सबसे सशक्त माध्यम सिद्ध होगी।भारत एक विकासशील देश है यदि हम 2047 तक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो युवा वर्ग जो छोटे शहरों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर छोटे शहरों में उद्यमिता प्रोत्साहन संबंधी सुविधाजनक माहौल उपलब्ध करवाना होगा तभी हम विकसित भारत की ओर अग्रसर होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References & Bibliography)

संदर्भ (References)

1 Ahlstrom, D. (2010). Innovation and growth: How business contributes to society in the developing world. Academy of Management Perspectives, 24(3), 11–24.

Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). (2023). Annual Report 2022-23. Government of India, New Delhi.

2 NITI Aayog. (2021). Building a Robust Startup Ecosystem in Tier-2 and Tier-3 Cities of India. Policy Brief Series, Government of India.

3 Sharma, R., & Kumar, P. (2020). Decentralized Entrepreneurship: A Catalyst for Rural-Urban Economic Balance. Indian Journal of Commerce & Management Studies, 11(2), 45–53.

4 DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade). (2022). States' Startup Ranking 2021: Fostering Entrepreneurship at Grassroots. Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

ग्रंथ सूची (Bibliography)

1 Chaudhary, A. (2019). Entrepreneurship and Regional Development in India. New Delhi: Concept Publishing Company.

2 Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). Entrepreneurship (10th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

3 Kumar, S. (2018). Rural and Youth Entrepreneurship in Madhya Pradesh: Dynamics and Challenges. Bhopal: Madhya Pradesh Institute of Social Science Research (MPISSR).

4 NASSCOM. (2022). Indian Tech Start-up Ecosystem: Year of The Titans (Focus on Emerging Hubs). NASSCOM Research, New Delhi.

5 Reserve Bank of India (RBI). (2021). Report of the Expert Committee on Micro, Small and Medium Enterprises (UK Sinha Committee). Mumbai: RBI Publications.

World Bank. (2020). India Development Update: Fostering Grassroots Innovation and Job Creation. Washington, DC: The World Bank Group.